>

Title: Need to modernize postal department to enable it to keep pace with private courier companies in the country.

प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) : अध्यक्ष जी, अंग्रेजों के समय से स्थापित केन्द्र सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक डाक विभाग आज अव्यवस्था और उदासीनता का शिकार है। डाक विभाग में केन्द्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं संचालित होती हैं, जिनमें लाडली लक्ष्मी, मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा विकास पत्र इत्यादि। विगत दस वर्षों में नगरों का विस्तार हुआ है, जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन पोस्टमैन्स की बीटों की संख्या कम कर दी गयी है। बड़ी संख्या में, पचास प्रतिशत से ज्यादा अस्थायी पोस्टमैन काम कर रहे हैं। डाक विभाग के इफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति खराब है। डाक भवन पुराने और जर्जर हैं। इतना ही नहीं डाक विभाग में जो कम्प्यूटर, सीपीयू और प्रिंटर भी काफी पुराने हैं। नेटवर्क भी कई बार काम नहीं करता है। इन सब के उन्नयन की बहुत आवश्यकता है। डाक विभाग की नीति के अनुसार सौ से अधिक रेल मेल सर्विस के छंटाई कार्यालय बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण स्पीड पोस्ट और साधारण डाक में देरी हो रही है।

आज बाजार में संचार के क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स और कोरियर सेवाएं बड़ी तेजी से बढ़ी हैं और इस तरह की कम्पनियों का प्रभुत्व देश की सुरक्षा के लिए भी प्रतिकूल है। अतः मेरा निवेदन है कि डाक विभाग के खाली पदों को तुरन्त भरा और साथ ही नये सिरे से नयी परिस्थितियों के अनुसार डाक व्यवस्था को बनाया जाए।